

कृषिक्षेत्र का सारांश (अगस्त 2026)

1. भविष्य का आधार कृषि

परिचय

स्वस्थ कृषि पद्धतियाँ खाद्य सुरक्षा को सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता एवं ग्रह के कल्याण से जोड़ती हैं जिससे कृषि एक रणनीतिक संस्था बन जाती है।

एक सभ्यतागत आधार के रूप में कृषि स्वास्थ्य

- ❖ कृषि कार्य भोजन एवं आजीविका प्रदान करने के साथ-साथ कार्बन अवशोषण, भूजल पुनर्भरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु विनियमन में भी योगदान देते हैं।
- ❖ मृदा क्षरण वैश्विक मृदा के लगभग 75% हिस्से को प्रभावित करता है जिससे जलवायु संबंधी अनिश्चितताओं के बीच खाद्य उत्पादन को खतरा पैदा हो रहा है।
- ❖ भारत की सिंचित कृषि के 60% से अधिक हिस्से को भूजल सहारा देता है जबकि जलभंडारों के कम होने से जल सुरक्षा कमजोर हो जाती है।
- ❖ कृषि क्षेत्र वैश्विक स्तर पर ताजे पानी की कुल निकासी का लगभग 70% और भारत में ताजे पानी की निकासी का लगभग 90% उपयोग करता है।
- ❖ सूक्ष्मजीवों, केंचुओं और परागणकर्ताओं की घटती संख्या जैव विविधता सेवाओं में कमी लाती है जिससे बाहरी इनपुट, सब्सिडी एवं सार्वजनिक लागत में वृद्धि होती है।
- ❖ आधुनिक फसलों में वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। 'आहार ही औषधि है' भोजन को निवारक चिकित्सा से जोड़ती है।



पुनर्योजी और जल-कुशल संक्रमण

- ❖ हरित क्रांति ने खाद्य आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की; वर्तमान प्राथमिकताओं में मृदा, जल, जैव विविधता और पोषण संबंधी बहाली की आवश्यकता है।
- ❖ जल-कुशल खेती में सटीक सिंचाई, जलक्षेत्र का पुनर्स्थापन, वर्षा जल संचयन, जलभंडार का पुनर्भरण और जलवायु के अनुकूल फसलें उगाना शामिल हैं।
- ❖ कृषि वानिकी, प्राकृतिक खेती और खाद्य वन जल संरक्षण करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं और खाद्य सुरक्षा में सुधार करते हैं।
- ❖ बाजरा, दालें, फल, सब्जियाँ व देसी अनाज मिलकर पारिस्थितिकी लचीलेपन और मानव पोषण में सुधार करते हैं।
- ❖ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उपग्रह इमेजरी, ड्रोन, सटीक सिंचाई, मौसम पूर्वानुमान और डिजिटल बाजार पारिस्थितिकी सीमाओं के भीतर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं।

नीतिगत प्राथमिकताएँ और भारत के अवसर

- ❖ जलवायु संबंधी अनिश्चितता, अस्थिर बाजार, बढ़ती लागत, खंडित जोत और श्रम की कमी किसानों की व्यवहार्यता एवं गरिमा को कम करती है।
- ❖ फसल उत्पादन के साथ-साथ मृदा, सिंचित जल, जैव विविधता, लचीलापन और पोषण के माध्यम से कृषि सफलता का आकलन करना।
- ❖ उपजाऊ भूमि, स्वस्थ जलक्षेत्रों और लचीले खेतों को राजमार्गों, बंदरगाहों व डिजिटल नेटवर्क के समान पारिस्थितिक अवसररचना के रूप में मान्यता देना।
- ❖ उत्पादन-केंद्रित सब्सिडी को एकीकृत कृषि, जल, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु नीतियों से बदलना जो पुनर्जनन को पुरस्कृत करती हैं।
- ❖ खरीद, वित्त, बीमा और अनुसंधान को मृदा कार्बन, भूजल पुनर्भरण, जैव विविधता, उत्सर्जन एवं पोषण विविधता के साथ संरेखित करना।
- ❖ भारत की कृषि-जलवायु विविधता, सहस्राब्दियों पुरानी कृषि पद्धतियाँ और बाजरा, मृदा स्वास्थ्य, जलसंभर, डिजिटल और प्राकृतिक खेती से संबंधित पहलें पुनर्योजी नेतृत्व को सक्षम बनाती हैं।

निष्कर्ष

लघु पारिस्थितिकी पदचिह्न और निम्न खाद्य दूरी के साथ संधारणीय सघनता कृषि को रणनीतिक सभ्यतागत संस्थानों के रूप में पुनर्स्थापित कर सकती है।

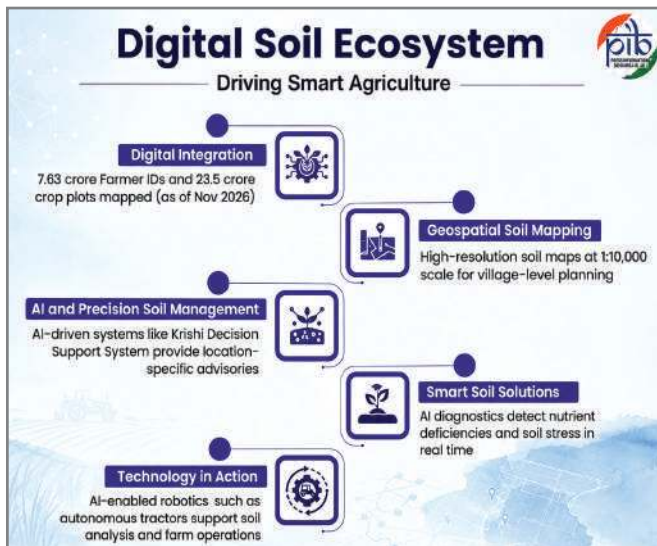
2. किसानों की रक्षा और भविष्य की सुरक्षा

परिचय

किसान कल्याण में आय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन, डिजिटल नवाचार और मजबूत बाज़ार शामिल हैं ताकि विकसित भारत@2047 को साकार किया जा सके।

संरचनात्मक प्रोफाइल और कृषि प्रदर्शन

- ❖ पिछले दशक में भारत की कृषि वृद्धि दर औसतन 4-4.5% प्रति वर्ष रही, जिससे उत्पादन में सुधार हुआ किंतु किसानों की आय में एक समान वृद्धि नहीं हुई।
- ❖ छोटे एवं सीमांत किसानों के पास 86.1% जोत हैं : एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान 68.5% और 1-2 हेक्टेयर भूमि वाले किसान 17.6% हैं।
- ❖ छोटे किसान कुल कृषि क्षेत्र के 47-48% हिस्से पर खेती करते हैं; कृषि 46% श्रमिकों का भरण-पोषण करती है और सकल बाज़ार मूल्य (GVA) में 18% का योगदान देती है।
- ❖ कृषि बजट 2013-14 में ₹27,663 करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹1,40,528.78 करोड़ हो गया है जो किसान-केंद्रित नीति को दर्शाता है।
- ❖ खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 में 265.05 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 के दौरान 357.73 मिलियन टन हो गया।
- ❖ बागवानी उत्पादन 2024-25 में 369.05 मिलियन टन तक पहुँच गया, जबकि 2026 की खरीफ की असमान वर्षा ने जलवायु संबंधी लगातार बनी रहने वाली भेद्यता को उजागर किया।



सरकारी सहायता और डिजिटल परिवर्तन

- ❖ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) आय सहायता प्रदान करती है; इसके एक-चौथाई लाभार्थी महिलाएँ हैं और 85% लघु किसान हैं।

- ❖ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) फसलों का बीमा करती है; किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि अवसंरचना कोष वित्तीय पहुँच का विस्तार करते हैं।
- ❖ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) मूल्य समर्थन, घाटा भुगतान, बाज़ार हस्तक्षेप और स्थिरीकरण निधि को एकीकृत करता है।
- ❖ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देती है, भूजल संरक्षण करती है और जल उपयोग दक्षता में सुधार करती है।
- ❖ स्वच्छ पादप कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन और श्वेत क्रांति 2.0 आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करते हैं।
- ❖ डिजिटल कृषि मिशन, वैयक्तिकृत कृषि सेवाओं के लिए एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइल मानचित्रण को एकीकृत करता है।

बाज़ार, समावेशन एवं अनुसंधान

- ❖ नवंबर 2025 तक 7.63 करोड़ किसान आईडी और 23.5 करोड़ भूखंड एआई, ड्रोन एवं भू-स्थानिक सलाह सेवाओं को सक्षम कर चुके होंगे।
- ❖ उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की 2016 की पहल स्टार्टअप इंडिया ने 2,096 कृषि स्टार्टअप्स को समर्थन दिया; वित्त वर्ष 2019-20-2025-26 के दौरान ₹168.14 करोड़ का अनुदान दिया गया।
- ❖ राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) से मूल्य निर्धारण में सुधार होता है; किसान उत्पादक संगठन (FPO) सौदेबाजी और बाज़ार संबंधों को मजबूत करते हैं।
- ❖ महिला किसानों को भूमि अधिकार, संस्थागत ऋण, प्रशिक्षण, बीमा एवं विस्तार की आवश्यकता होती है; स्वयं सहायता समूह ग्रामीण उद्यमशीलता को मजबूत करते हैं।
- ❖ बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम, रेशम उत्पादन, कृषि वानिकी और खाद्य प्रसंस्करण में विविधता लाने से उत्पादन संबंधी जोखिम कम हो जाते हैं।
- ❖ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद लचीली फसलों को बढ़ावा दे रही है; अनुसंधान पर खर्च जीडीपी का 0.5% बना हुआ है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह 2-5% है।

निष्कर्ष

निरंतर निवेश और साझेदारी से कृषि को उत्पादक, लाभदायक एवं लचीला बनाया जा सकता है, जिससे प्रत्येक किसान विकास भागीदार के रूप में स्थापित हो सके।

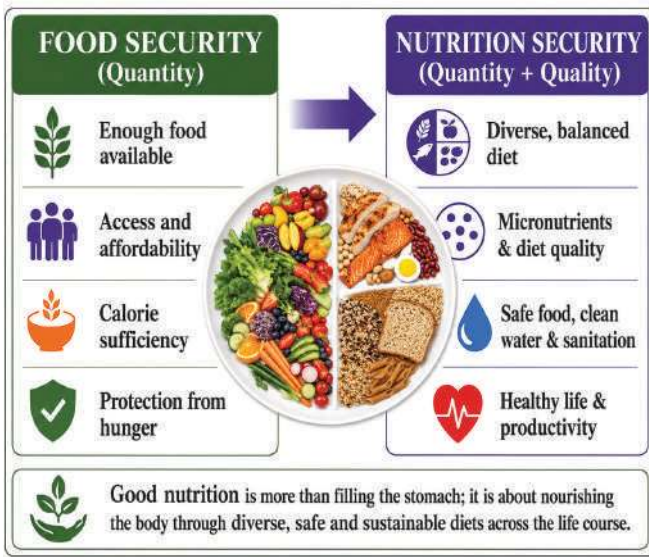
3. खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक

परिचय

पोषण सुरक्षा के लिए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा एवं महिला सशक्तीकरण सहित बहुक्षेत्रीय समन्वय की आवश्यकता है।

पोषण संबंधी चुनौतियों को समझना

- ❖ हरित क्रांति, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, फसलों की किस्मों एवं वितरण ने खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित की है किंतु सार्वभौमिक पोषण सुरक्षा नहीं।
- ❖ खाद्य सुरक्षा पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करती है; पोषण सुरक्षा के लिए विविध आहार, सुरक्षित पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और देखभाल की आवश्यकता भी होती है।
- ❖ पर्याप्त कैलोरी उपलब्ध होने के बावजूद भारत कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, अधिक वजन और मोटापे के तिहरे बोझ का सामना कर रहा है।
- ❖ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार की रिपोर्ट है किंतु आहार विविधता और स्वस्थ खानपान में लगातार कमियाँ पाई गई हैं।
- ❖ पहले 1,000 दिनों में प्रोटीन, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है; इनकी कमी से बौनापन, एनीमिया व कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।



सरकारी पहल

- ❖ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से लगभग दो-तिहाई लोगों को रियायती अनाज की आपूर्ति की जाती है।
- ❖ वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) प्रवासी परिवारों को देशभर में उचित मूल्य की दुकानों से रियायती दरों पर अनाज प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- ❖ सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 पहले 1,000 दिनों के दौरान जीवनचक्र पोषण, निगरानी एवं परामर्श प्रदान करते हैं।
- ❖ पीएम पोषण कार्यक्रम स्थानीय खाद्य पदार्थों का उपयोग करके स्कूली भोजन में सुधार करता है, जैसे- कर्नाटक की रागी, ओडिशा का बाजरा, तमिलनाडु की सब्जियाँ-दालें, अंडे या दूध।

- ❖ 'श्री अन्न' की किस्में-रागी, बाजरा एवं ज्वार-पोषण को बेहतर बनाती हैं; ओडिशा मिलेट मिशन विविधता, जैव-विविधता व आजीविका को मजबूत करता है।
- ❖ TPDS, पीएम पोषण एवं आँगनवाड़ियों के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल से आयरन, फोलिक एसिड व बी12 की आपूर्ति होती है; एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम इन कमियों को दूर करता है।

स्वस्थ खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र

- ❖ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ईट राइट इंडिया और ईट राइट कैंपस का नेतृत्व करता है जिसका उद्देश्य अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को कम करना है।
- ❖ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित पंखुड़ी पोर्टल पोषण शिक्षा के लिए शिक्षा जगत, नागरिक समाज व कॉर्पोरेट पहलों को आपस में जोड़ता है।
- ❖ ICMR-राष्ट्रीय पोषण संस्थान के 2024 के दिशा-निर्देश अनाज, बाजरा, दालों एवं फलों-सब्जियों को प्राथमिकता देते हैं जबकि चीनी, नमक व अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को सीमित करते हैं।
- ❖ रिफाईंड आटे और तले हुए स्नैक्स की जगह बाजरे का आटा, अंकुरित अनाज और किण्वित खाद्य पदार्थों का सेवन करना तथा पैकेटबंद स्नैक्स की जगह फलों को चुनना चाहिए।
- ❖ सप्ताह में एक बार श्री अन्न दिवस मनाना और इंद्रधनुषी रंग की थाली का सेवन करना चाहिए; मीठे पेय पदार्थों के बजाय छाछ, नींबू पानी या नारियल पानी को प्राथमिकता देना लाभप्रद है।
- ❖ स्कूलों, कार्यस्थलों और घरों को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से मौसमी खाद्य पदार्थों, रसोई उद्यानों एवं सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

समन्वित बहुक्षेत्रीय कार्रवाई और बेहतर घरेलू आहार सभी के लिए पोषण सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं जिससे 2047 तक विकसित भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है।

4. जलवायु-अनुकूल कृषि की ओर

परिचय

स्वस्थ मृदा, संतुलित पोषक तत्व, जल दक्षता एवं डिजिटल विस्तार जलवायु-लचीली कृषि की नींव का निर्माण करते हैं।

खेत बचाओ अभियान

- ❖ सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने 1 से 30 जून, 2026 के दौरान खेत बचाओ अभियान चलाया।
- ❖ मिट्टी बचाओ, खेती बचाओ, किसान बचाओ अभियान ने मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक प्रयोग, जल संरक्षण एवं जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा दिया।
- ❖ इस अभियान के तहत 31,821 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 46.01 लाख से अधिक हितधारकों तक पहुँचा गया और 4.66 करोड़ डिजिटल इंटरैक्शन किए गए।

- ❖ भारत के सबसे बड़े कृषि विस्तार अभियान में ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, विश्वविद्यालयों, विभागों एवं किसान समूहों को शामिल किया गया।
- ❖ 30 जून, 2026 को हरियाणा में शिवराज सिंह चौहान ने इसे एक सतत राष्ट्रीय मिशन में परिवर्तित करने की घोषणा की।
- ❖ बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ एवं लू के कारण पैदावार और गुणवत्ता में कमी आती है जिससे छोटे किसानों की आजीविका खतरे में पड़ जाती है (IPCC 2023)।



वैज्ञानिक एवं डिजिटल हस्तक्षेप

- ❖ मृदा स्वास्थ्य जैविक, रासायनिक और भौतिक अखंडता को एकीकृत करता है; सूक्ष्मजीव, कवक और केंचुए पोषक तत्वों के चक्रण एवं जल प्रतिधारण को बनाए रखते हैं।
- ❖ राष्ट्रीय आकलन से पता चलता है कि भारत की 64% मृदा में नाइट्रोजन की कमी है और 48.5% में कार्बनिक कार्बन का स्तर कम है, जिससे तनाव सहने की क्षमता कमजोर हो जाती है।
- ❖ मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) बारह रासायनिक-भौतिक मापदंडों का आकलन करता है और फसल-वार मोबाइल सलाह के माध्यम से संतुलित उर्वरक प्रयोग में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

- ❖ एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) में खाद, कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक एवं रसायनों का संयोजन होता है जिससे पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता में सुधार होता है।
- ❖ इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और भौगोलिक सूचना प्रणाली संसाधनों के उपयोग की दक्षता में सुधार करते हैं।
- ❖ कृषि सखी और नमो ड्रोन दीदी ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन, मृदा के नमूने लेने, कस्टम सेवाओं और कृषि-उद्यमिता में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

नीति अभिसरण और परिणाम

- ❖ राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, सतत कृषि और प्राकृतिक खेती मिशनों के साथ-साथ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का पूरक है।
- ❖ इस पद्धति को अपनाने में आने वाली बाधाओं में सीमित मृदा परीक्षण, जटिल SHC परामर्श, खंडित जोत, निम्न मशीनीकरण, खराब इनपुट और भूजल की कमी शामिल हैं।
- ❖ अनुसंधान, डिजिटल साक्षरता, मजबूत बाजार, जलवायु-लचीली किस्में और किसान-केंद्रित विस्तार को संदर्भ-विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर लागू करना चाहिए।
- ❖ सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2030 इस अभियान को शून्य भूख और स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से जोड़ते हैं।
- ❖ कार्बन पृथक्करण और जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, अनुकूलन एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण व भूमि पर जीवन को बढ़ावा देते हैं।
- ❖ स्वस्थ मृदा, कुशल संसाधन, तकनीकी नवाचार और किसान सशक्तीकरण जलवायु-लचीली कृषि और 2047 के दौरान विकसित भारत के आधारभूत तत्व हैं।

निष्कर्ष

मृदा स्वास्थ्य को बचाना कृषि उत्पादकता, प्राकृतिक संसाधनों और ग्रामीण आजीविका की रक्षा करता है जिससे एक लचीला व टिकाऊ कृषि भविष्य सुनिश्चित होता है।

5. कृषि विरासत : भारत की चिरस्थायी विरासत से विकसित भारत तक

परिचय

भारत की कृषि विरासत सतत विकास के लिए जीवित ज्ञान, जैव विविधता और सामुदायिक प्रणालियों को विज्ञान और नवाचार के साथ जोड़ती है।

ऐतिहासिक ज्ञान और जैव विविधता

- ❖ सिंधु-सरस्वती सिंचाई, भंडारण एवं फसलों से प्रमाणित भारत की 5,000 साल पुरानी कृषि विरासत सभ्यता को पारिस्थितिकी ज्ञान से जोड़ती है।

- ❖ क्षेत्रीय विविधता में हिमालयी सीढ़ीदार खेत, राजस्थान के शुष्क क्षेत्र, गंगा की सिंचाई, पूर्वोत्तर की मिश्रित खेती और दक्षिण भारतीय जल आधारित प्रणालियाँ शामिल हैं।
- ❖ मिश्रित खेती, फसल चक्र, कृषि वानिकी, एकीकृत पशुधन, जैविक खाद और प्राकृतिक कीट प्रबंधन संसाधन संतुलन को बनाए रखते हैं।
- ❖ हजारों स्वदेशी चावल, बाजरा, दाल और तिलहन की किस्में सूखा, बाढ़, लवणता एवं तापमान में बदलाव को सहन कर सकती हैं।
- ❖ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो सामुदायिक बीज बैंकों के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण करते हैं।
- ❖ 17 मेगा जैव-विविधता वाले देशों में से एक होने के नाते भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के दौरान विभिन्न प्रकार के बाजरा को बढ़ावा दिया।

क्षेत्रीय प्रणालियाँ और सांस्कृतिक मूल्य

- ❖ परंपरागत जल प्रणालियों में राजस्थान की जोहड़-खादिन-बाओली, हिमाचल की कुहल, बिहार की आहार-पायने, मेघालय की बांस-ड्रिप सिंचाई और दक्षिण भारतीय टैंक सिंचाई शामिल हैं।
- ❖ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 'हर खेत को पानी' को उन्नत करते हुए सूक्ष्म सिंचाई को पुनर्जीवित जल प्रणालियों के साथ जोड़ती है।
- ❖ खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त कोरापुट प्रणाली, जो विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली है, स्वदेशी चावल और सामुदायिक जैव विविधता का संरक्षण करती है।
- ❖ अपातानी चावल-फिश फार्मिंग, नागालैंड का जाबो और समुद्र तल से नीचे स्थित कुट्टानाड एकीकृत संसाधन उपयोग और पारिस्थितिकी संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
- ❖ पोंगल, बैसाखी, माघ बिहू, नुआखाई, ओणम और मकर संक्रांति फसल परंपराओं, कृतज्ञता एवं सामुदायिक सहयोग को संरक्षित करते हैं।
- ❖ भौगोलिक संकेतक द्वारा संरक्षित दार्जिलिंग चाय, बासमती चावल, कश्मीरी केसर, कंधमाल हल्दी, नागपुर संतरा, मिथिला मखाना रोजगार एवं निर्यात को बढ़ावा देते हैं।

एकीकरण और संरक्षण प्राथमिकताएँ

- ❖ प्राकृतिक खेती मिशन, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करती है।
- ❖ डिजिटल कृषि मिशन संसाधन दक्षता के लिए डेटाबेस, फसल सर्वेक्षण, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रिमोट सेंसिंग और भू-स्थानिक सलाह का उपयोग करता है।
- ❖ संरक्षण के लिए खतरों में भूमि का विखंडन, भूजल का अत्यधिक उपयोग, कृषि रसायनों पर निर्भरता, लुप्त होते बीज, मौखिक ज्ञान का क्षरण और जलवायु की चरम स्थितियाँ शामिल हैं।

- ❖ सामुदायिक-विश्वविद्यालय साझेदारी के माध्यम से प्रलेखन और वैज्ञानिक सत्यापन से बीज बैंकों, जल प्रणालियों, कृषि शिक्षा एवं स्थानीय ज्ञान को मजबूती मिलनी चाहिए।
- ❖ पारंपरिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, डिजिटल उपकरणों और सार्वजनिक नीति के संयोजन से विकसित भारत के लिए उत्पादक एवं लचीली कृषि का निर्माण किया जा सकता है।

निष्कर्ष

कृषि विरासत का संरक्षण खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन और ग्रामीण समृद्धि को मजबूत करता है। साथ ही, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखता है।

6. संरचनात्मक नवाचार के माध्यम से कृषि को सुदृढ़ बनाना

परिचय

भारत का कृषि परिवर्तन छोटे किसानों की लचीलता सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों, वैज्ञानिक अनुसंधान, पारिस्थितिक सुधार और डिजिटल नवाचार को एक साथ जोड़ता है।

खाद्य की कमी से खाद्य सुरक्षा की ओर

- ❖ कृषि-पराशर (छठी शताब्दी ईस्वी) और वृक्षायुर्वेद (ग्यारहवीं शताब्दी ईस्वी) ने कृषि विज्ञान, मृदा वर्गीकरण और बीज उपचार को संहिताबद्ध किया।
- ❖ औपनिवेशिक शोषण और वाणिज्यिक एकल-कृषि पद्धतियों ने 1859-60 के नील विद्रोह को जन्म दिया, जबकि 1876-78 और 1943 के दौरान पड़े अकाल ने लाखों लोगों की जान ले ली।
- ❖ 1947 में 340 मिलियन लोगों के लिए खाद्यान्न का उत्पादन 50 मिलियन टन था, जो 2025-26 में बढ़कर 376.56 मिलियन टन हो गया।
- ❖ 1951 के प्रथम संशोधन ने नौवीं अनुसूची के माध्यम से प्रारंभिक भूमि सुधारों को संरक्षण प्रदान किया; आज 85% से अधिक किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है।
- ❖ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 74 विश्वविद्यालय, 110 से अधिक संस्थान और 70 पशु चिकित्सा महाविद्यालय शामिल हैं जो वैज्ञानिक क्षमता का निर्माण कर रहे हैं।
- ❖ सोनालिका, कल्याण सोना, IR-8, नहरों, उर्वरकों एवं एमएसपी के माध्यम से गेहूँ का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर 120.66 मिलियन टन (1960-61 से 2025-26) हो गया।

सहकारी समितियाँ और विविधीकरण

- ❖ सरदार पटेल और त्रिभुवनदास पटेल के शासनकाल में 14 दिसंबर, 1946 को पंजीकृत अमूल को मई 1949 में वर्गीज कुरियन की विशेषज्ञता प्राप्त हुई।
- ❖ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया; दूध का उत्पादन 17 मिलियन टन से बढ़कर 247.87

- मिलियन टन हो गया, जो वैश्विक हिस्सेदारी का 25% तक पहुँच गया।
- नीली क्रांति के कारण 2024-25 में मछली उत्पादन में 106% की वृद्धि हुई और यह 197.75 लाख टन तक पहुँच गया; समुद्री भोजन का निर्यात ₹62,408 करोड़ तक पहुँच गया।
- बागवानी का उत्पादन 2025-26 में 370.85 मिलियन टन तक पहुँच गया; पशुधन एवं मत्स्य पालन में क्रमशः 7.1% और 8.8% की वृद्धि हुई, जिससे छोटे किसानों की आय में विविधता आई।
- कृषि से संबंधित सकल मूल्य वर्धित (GVA) 2023-24 में ₹48.77 लाख करोड़ तक पहुँच गया; पशुधन का योगदान 30.87% रहा, जिससे परिवारों की लचीलापन मजबूत हुआ।
- श्री अन्न का उत्पादन 2025-26 में 17.584 मिलियन टन और मक्का का उत्पादन 55.093 मिलियन टन होने का अनुमान है।

All you want to know about

Namo Drone Didi



-  A central sector scheme empowering women-led Self-Help Groups (SHGs)
-  Providing SHGs with drone technology for agricultural services
-  Target to equip 15,000 Women SHGs with drones (2024-26) for providing rental services to farmers for agriculture purpose
-  Expected to generate a minimum additional income of ₹1 lakh annually for each SHG

- प्रति बूँद अधिक फसल, 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड और नैनो-यूरिया संसाधनों की दक्षता में सुधार करते हैं जिससे रासायनिक अपवाह एवं निर्भरता कम होती है।
- राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन द्वारा समर्थित HRMN-99 को 25 राज्यों में अपनाया गया; हरिमन शर्मा को 2017 का नवाचार पुरस्कार और 2025 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- एग्रीस्टैक, जो किसान रजिस्ट्री, भू-संदर्भित मानचित्रों एवं बोई गई फसल की रजिस्ट्री को एकीकृत करता है, ने महाराष्ट्र के 89 लाख किसानों को ₹14,000 करोड़ का मुआवजा देने में सक्षम बनाया।
- भारत-विस्तार योजना, जिसके लिए 2026-27 में 150 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है, को फरवरी 2026 में भारती एआई, बहुभाषी वॉयस एक्सेस और दस योजनाओं के एकीकरण के साथ लॉन्च किया गया था।
- नमो ड्रोन दीदी परियोजना, ₹1,261 करोड़ की लागत से, 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को लक्षित करती है, 80% सब्सिडी; जनवरी 2026 तक 1,094 ड्रोन वितरित किए गए।

निष्कर्ष

वैज्ञानिक संस्थानों, जमीनी स्तर पर नवाचार, डिजिटल पहुँच और संसाधन संरक्षण को एकीकृत करने से 2047 तक समावेशी, टिकाऊ कृषि का निर्माण हो सकता है।

7. सतत कृषि में महिलाओं का योगदान

परिचय

सामूहिक संगठनों, प्रौद्योगिकी, कानूनी मान्यता और बाजार से जुड़े उद्यमों के माध्यम से महिला किसान गैर-मान्यता प्राप्त मजदूरों से नेतृत्वकर्ताओं की ओर अग्रसर हो रही हैं।

महिलाओं की भागीदारी का पैमाना

- संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में नामित किया है जिसमें महिलाओं को उत्पादक, उद्यमी एवं कृषि संबंधी निर्णय लेने वाली संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई है।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.91 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया, जिससे उन्हें 12 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त हुआ।
- महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना ने 70,000 कृषि सखियों में से 34,000 को प्रमाणित किया; 2022 से 2.5 करोड़ महिलाओं ने कृषि-पारिस्थितिकी प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ने 28 फरवरी, 2026 तक 2025-26 के दौरान 11.61 लाख महिला किसानों को प्रशिक्षण दिया।
- महिला कार्यबल की हिस्सेदारी 2017-18 में 57% से बढ़कर 2023-24 में 64.4% हो गई, फिर भी वे केवल 14% हिस्सेदारी का संचालन करती हैं।

पारिस्थितिकी और डिजिटल नवाचार

- केंद्रीय भूजल बोर्ड के 2025 के आकलन में जल स्तर में कमी पाई गई; पश्चिम बंगाल के 346 क्लस्टरों से 2026-27 के दौरान 43,250 किसानों को लाभ मिलेगा।

- ❖ लखपति दीदी मिशन ने तीन करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए से अधिक कमाने में सक्षम बनाया है और इसका लक्ष्य 2029 तक छः करोड़ महिलाओं तक पहुँचना है।

EMPOWERING WOMEN FARMERS

Key Takeaways



India empowers women farmers through an integrated framework of schemes, covering financial support, affordable credit, improved infrastructure, advanced technology, Training, and skill development.



In 2025-26 (Up to 28.02.26), over **11.61 lakh** women farmers were trained and capacitated under the Agricultural Technology Management Agency (ATMA) scheme.



Agricultural Infrastructural Fund (AIF) and Namo Drone Didi expanded access to credit, technology, and training, supporting **8,190 women-led projects** worth **Rs 2,377 crore**.



Women-led Farmers Producer Organizations (FPOs) are growing, with **1175 all-women FPOs** benefiting **23.55 lakh farmers**.



Under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme, over **Rs 1.01 lakh crore** has been disbursed to **women beneficiaries** since the inception of the Scheme.



The **Krishi Sakhi** initiative enhances women's skills, training, and access to resources in the agricultural sector.

लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए; 2.15 करोड़ महिलाओं को 22वीं किस्त प्राप्त हुई।

- ❖ कृषि अवसंरचना कोष ने 2,377 करोड़ रुपए मूल्य की 8,190 महिला नेतृत्व वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है; कृषि विपणन अवसंरचना ने 10,600 से अधिक भंडारण परियोजनाओं को सहायता प्रदान की।

सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र और प्राथमिकताएँ

- ❖ नमो ड्रोन दीदी के 1,261 करोड़ रुपए के निवेश से महिलाओं की ड्रोन सेवाओं को बढ़ावा मिला; 1,175 महिला किसान उत्पादक संगठनों से 23.55 लाख किसानों को लाभ हुआ।
- ❖ संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना और किसान क्रेडिट कार्ड से संस्थागत ऋण का विस्तार हुआ है; MANAGE ने 2020 से अब तक 61,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है।
- ❖ महिलाओं के पास 56% जन धन खाते और 68% मुद्रा ऋण हैं जबकि 33% विधायी आरक्षण राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करता है।
- ❖ मार्च 2026 में आयोजित वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणाली महिला सम्मेलन ने महिलाओं के नेतृत्व को खाद्य सुरक्षा एवं जलवायु अनुकूलन क्षमता से जोड़ा है।
- ❖ लिंग-संवर्धनशील भूमि अभिलेख, संयुक्त स्वामित्व और विरासत सुधारों को ऋण, बीमा एवं योजनाओं को वास्तविक खेती से जोड़ना चाहिए।
- ❖ जलवायु-अनुकूल कृषि, सिंचाई, भंडारण, मशीनीकरण, डिजिटल विस्तार, FPO और प्रसंस्करण में निवेश महिलाओं को कृषि व्यवसाय की अग्रणी हस्तियों में बदल सकता है।

निष्कर्ष

खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और विकसित भारत के लिए महिलाओं को किसान एवं निर्णय लेने वाली संस्थाओं के रूप में मान्यता देना अत्यावश्यक है।

8. कृषि के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में

परिचय

भारत को उत्पादन को अधिकतम करने के बजाय समन्वित दीर्घकालिक निवेशों के माध्यम से लचीली, लाभदायक एवं पारिस्थितिक रूप से पुनर्जीवित करने वाली कृषि की ओर बढ़ना होगा।

कृषि प्रगति को पुनर्परिभाषित करना

- ❖ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र लगभग 46% श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं किंतु राष्ट्रीय आय का पाँचवाँ हिस्सा ही उत्पन्न करते हैं जिससे उत्पादकता में कमी प्रदर्शित होती है।
- ❖ कृषि प्रगति को कृषि आय, उपज स्थिरता, मृदा कार्बन, जल उत्पादकता, पोषण, समावेशन और जलवायु भेद्यता के माध्यम से मापना चाहिए।

राज्य स्तरीय मॉडल और राष्ट्रीय समर्थन

- ❖ एकीकृत बेसिन विकास एवं आजीविका संवर्धन कार्यक्रम ने वसंत ऋतु में भूमि को पुनर्जीवित करने, ड्रिप सिंचाई और उच्च मूल्य वाली फसलों के माध्यम से मेघालय के किसानों का रूपांतरण किया।
- ❖ वर्ष 2016 से दुनिया के पहले पूरी तरह से जैविक राज्य सिक्किम में महिलाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त ज्ञान के माध्यम से इलायची, अदरक एवं हल्दी का व्यावसायीकरण किया है।
- ❖ महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तीकरण अधिनियम, जुलाई 2026, बिना मालिकाना हक वाले किसानों को मान्यता देता है और प्रमाण पत्र, राज्य निधि एवं डिजिटल डेटाबेस का निर्माण करता है।
- ❖ तेलंगाना के 33 जिलों में 4.35 लाख महिला समूहों को ₹12.66 करोड़ का चैलेंज फंड प्राप्त हुआ, जिससे खाद्य प्रसंस्करण, संबद्ध एवं हस्तशिल्प उद्यमों को वित्तपोषण प्राप्त हुआ।
- ❖ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत महिलाओं को 1.01



- ❖ अनुकूलन के बिना 2050 तक वर्षा आधारित धान की पैदावार में 20% और गेहूँ की पैदावार में 19.3% की गिरावट आ सकती है जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन आवश्यक हो जाता है।
- ❖ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2025 में 300 से अधिक जिलों को अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में रखा है और जिला स्तर पर आकस्मिक योजना बनाने की मांग की है।
- ❖ स्वस्थ मृदा जल, पोषक तत्वों एवं जैव-विविधता का भंडार करती है; मृदा स्वास्थ्य कार्ड को जैविक पदार्थ को बहाल करने वाले क्षेत्र-विशिष्ट उपकरण के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
- ❖ दलहन, खाद, कम्पोस्ट, अवशेष एवं जैव-उर्वरकों का उपयोग करके एकीकृत उर्वरक प्रयोग से पोषक तत्वों की दक्षता, मृदा कार्बन व उत्पादकता में सुधार होता है।



- ❖ डिजिटल कृषि मिशन, एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा मानचित्रण कीट निगरानी, बीमा, पूर्वानुमान एवं बाजारों को सक्षम बनाते हैं।
- ❖ किसान-केंद्रित डिजिटलीकरण के लिए किफायती स्थानीय भाषा सेवाओं, सहमति, सुधार, सुवाह्यता, गोपनीयता एवं भौतिक डिजिटल माध्यमों से मानव विस्तार की आवश्यकता होती है।

संस्थागत और निम्न-कार्बन संक्रमण

- ❖ किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, जल उपयोगकर्ता संघ और प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ संसाधनों को एकत्रित करके सामूहिक स्तर की क्षमता प्राप्त करती हैं।
- ❖ चक्र्रीय जैव-अर्थव्यवस्थाएँ अवशेषों, खाद और प्रसंस्करण अपशिष्ट को कम्पोस्ट, पशु आहार, बायोचार व बायोगैस में परिवर्तित करती हैं; नवीकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन को कम करती हैं।
- ❖ नीति आयोग के 2026 के परिदृश्यों में पोषक तत्व प्रबंधन, विविधीकरण, कुशल ऊर्जा और टिकाऊ चावल को कृषि उत्सर्जन में कमी से जोड़ा गया है।
- ❖ महिलाओं को भूमि, वित्त, मशीनरी एवं नेतृत्व की आवश्यकता है; ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से ड्रोन, मृदा स्वास्थ्य, सिंचाई व डेटा कौशल की आवश्यकता है।
- ❖ खरीद एवं न्यूनतम समर्थन से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए जबकि प्रोत्साहन विविधीकरण, पुनर्स्थापन, अनुसंधान और जोखिम न्यूनीकरण की ओर स्थानांतरित होने चाहिए।
- ❖ जिला योजनाओं और सार्वजनिक डैशबोर्ड को 2047 तक लाभप्रदता, भूजल, मृदा स्वास्थ्य, नुकसान, लचीलापन एवं समावेशिता पर निगरानी रखनी चाहिए।

निष्कर्ष

स्वस्थ मृदा, सुरक्षित जल, जिम्मेदार प्रौद्योगिकी और निष्पक्ष बाजारों को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय कृषि समझौता स्वस्थ खेत और स्वस्थ ग्रह के लक्ष्य को साकार कर सकता है।

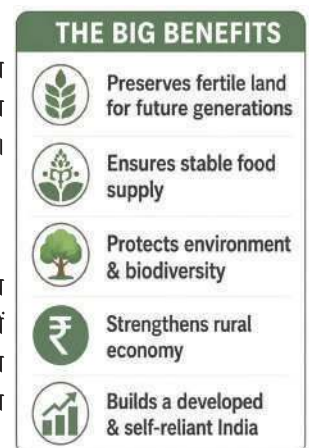
9. उत्तरदायित्वपूर्वक वृद्धि करना

परिचय

‘सेव द फार्म कैम्पेन’ कृषि भूमि संरक्षण और मृदा पुनर्स्थापन को खाद्य सुरक्षा एवं जिम्मेदार शहरीकरण से जोड़ता है।

कृषि भूमि संरक्षण की अति आवश्यकता

- ❖ हरित क्रांति ने खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है किंतु रसायनों के अत्यधिक उपयोग से मृदा की अवस्था और लाभकारी जीव नष्ट हो गए हैं।



संसाधन-कुशल और विविधीकृत खेती

- ❖ जलसंभर का पुनर्स्थापन, जल संचयन, पुनर्भरण, सूक्ष्म सिंचाई और बारी-बारी से आर्द्रता-शुष्कता करने से प्रति बूँद अधिकतम मूल्य प्राप्त होता है; सौर सिंचाई के लिए भूजल की निगरानी आवश्यक है।
- ❖ अट्टानवे मेटा-विश्लेषणों में पाया गया कि विविधीकरण से पैदावार कम किए बिना जैव विविधता, परागण, कीट नियंत्रण, मृदा की उर्वरता और जल नियमन में सुधार होता है।
- ❖ फसल-पशुधन-मछली-वृक्ष प्रणालियाँ पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करती हैं, साल भर रोजगार प्रदान करती हैं और जोखिम को कम करती हैं; इनकी व्यवहार्यता के लिए ऋण, बीमा, भंडारण एवं बाजारों की आवश्यकता होती है।
- ❖ जीनोमिक चयन, तीव्र प्रजनन और सहभागी चयन प्रजनन चक्रों को छोटा करते हैं; सामुदायिक बीज प्रणालियाँ स्थानीय रूप से अनुकूलित विविधता का संरक्षण करती हैं।

- ❖ भारत वैश्विक जनसंख्या के 18% और पशुधन के 15% का भरण-पोषण करता है जबकि वैश्विक भूमि का केवल 2.4% हिस्सा ही उपयोग करता है।
- ❖ इंडिपेंडेंस में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता 0.5 हेक्टेयर थी, जो आज घटकर 0.12 हेक्टेयर से भी कम हो गई है।
- ❖ दिल्ली, मुंबई एवं बंगलुरु के आसपास शहरी विस्तार के कारण उपजाऊ भूमि भवनों व रियल एस्टेट परियोजनाओं में परिवर्तित हो रही है।
- ❖ कर्ज, अनिश्चित मानसून और अस्थिर आय भूमि की बिक्री को प्रोत्साहित करते हैं जिससे अपरिवर्तनीय नुकसान होता है और खाद्य सुरक्षा कमजोर होती है।
- ❖ रोम एवं मेसोपोटामिया का पतन यह दर्शाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का लंबे समय तक क्षरण उन्नत सभ्यताओं को कमजोर कर सकता है।

अभियान रणनीति और भूमि प्रशासन

- ❖ विशेष कृषि क्षेत्र (SAZ) दो-तीन वार्षिक फसलों का उत्पादन करने वाली उपजाऊ भूमि को अनियोजित शहरीकरण से बचाते हैं।
- ❖ मृदा स्वास्थ्य कार्ड, गोबर की खाद, वर्मीकम्पोस्ट और जीवामृत उर्वरता, सूक्ष्मजीवों एवं दीर्घकालिक उत्पादकता को बहाल करते हैं।
- ❖ गेहूँ-चावल के चक्रों को दलहन और तिलहन की खेती से बदलने से नाइट्रोजन की भरपाई होती है जिससे कृत्रिम उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाती है।
- ❖ विकास में बंजर, परती एवं निम्नीकृत भूमि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसे जिप्सम, वनीकरण और जल प्रबंधन के माध्यम से पुनर्स्थापित किया जा सके।
- ❖ चीन की रेड-लाइन नीति न्यूनतम कृषि भूमि की सुरक्षा करती है; जापान लाइसेंस प्राप्त किसानों तक ही खरीद को सीमित करता है जिससे सट्टेबाजी पर रोक लगती है।
- ❖ 73वें संवैधानिक संशोधन से ग्राम पंचायतों को अधिकार प्राप्त हुए हैं; डिजिटल रिकॉर्ड, भू-स्थानिक मानचित्रण और उपग्रहों से भूमि उपयोग की जवाबदेही मजबूत होती है।

किसान-नेतृत्व वाले और प्रौद्योगिकी-सक्षम मार्ग

- ❖ लैंड पूलिंग, दीर्घकालिक पट्टा एवं उद्योग साझेदारी से आवर्ती आय उत्पन्न होती है जबकि किसान अपनी पैतृक संपत्ति का स्वामित्व बनाए रखते हैं।
- ❖ रिवर्स माइग्रेशन शिक्षित युवाओं को ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर और सटीक कृषि के साथ खेती में संलग्न कर रहा है।
- ❖ हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और मोबाइल सिस्टम उच्च मूल्य वाली खेती, दूरस्थ सिंचाई निगरानी और स्थान-कुशल उत्पादन को संभव बनाते हैं।
- ❖ एग्री-स्टार्टअप, डिजिटल कृषि और जलवायु-अनुकूल खेती संरक्षित भूमि को ग्रामीण समृद्धि का इंजन बना सकते हैं।

- ❖ दीर्घकालिक सफलता के लिए सुदृढ़ कानून, जिम्मेदार शासन और नागरिक भागीदारी आवश्यक है। साथ ही, विकास को पारिस्थितिकी सीमाओं के भीतर रखना भी जरूरी है।

निष्कर्ष

उत्तरदायी वृद्धि के लिए हर भोजन और आजीविका को बनाए रखने वाली उपजाऊ मृदा की सुरक्षा करना आवश्यक है जिससे कृषि भूमि संरक्षण एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता बन जाती है।

10. नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

परिचय

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा 2015 में शुरू की गई 'एस्पायर योजना' ग्रामीण कौशल और संसाधनों को उद्यमों में परिवर्तित करती है।

योजना डिजाइन और इनक्यूबेशन आर्किटेक्चर

- ❖ नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (ASPIRE) ग्रामीण उद्यम सृजन व रोजगार को बढ़ावा देती है।
- ❖ वर्ष 2018 के दिशा-निर्देशों ने इनक्यूबेशन को मजबूत किया, जबकि 2023 के संशोधनों ने आजीविका, उद्यमों एवं मापने योग्य परिणामों को प्राथमिकता दी।
- ❖ आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (LBI) आधुनिक उपकरण एवं मार्गदर्शन, प्रौद्योगिकी, मान्यता, अनुपालन, वित्त व बाजार संपर्क प्रदान करते हैं।
- ❖ सतत सहयोग के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना योजना संचालन समिति, मेंटर संस्थानों एवं मेजबान संस्थानों को जोड़ती है।
- ❖ मेंटर संस्थान इनक्यूबेटर्स की पहचान करते हैं, परियोजनाएँ तैयार करते हैं, कार्यक्रम डिजाइन करते हैं, कार्यान्वयन को मजबूत करते हैं और परिणामों की निगरानी करते हैं।
- ❖ गुवाहाटी स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (IIE), कृषि विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान एवं आईआईटी जोधपुर कृषि-उद्योग इनक्यूबेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पहुँच, क्षेत्र और समावेशन

- ❖ जून 2026 तक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 109 एलबीआई ने 1.23 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2022-23 से इनक्यूबेटर्स ने 1,200 से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को सुविधा प्रदान की है, जिससे कौशल को आजीविका में परिवर्तित किया जा सके।
- ❖ ASPIRE ने 28,500 से अधिक महिलाओं के लिए अवसर सृजित किए हैं जिससे देशभर में उद्यम निर्माण में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार हुआ है।
- ❖ इसकी व्यापक पहुँच में 8,700 अनुसूचित जाति, 9,600 अनुसूचित जनजाति और 17,600 अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी शामिल थे।

- ❖ एलबीआई खाद्य प्रसंस्करण, शहद, बाँस और मशरूम के साथ-साथ मसालों, हस्तशिल्प व नारियल के रेशे से बने उत्पादों का समर्थन करते हैं।
- ❖ प्रसंस्करण, विनिर्माण एवं मूल्यवर्धन ग्रामीण उत्पादकों को बड़ी शृंखलाओं में एकीकृत करते हैं जिससे आय सृजन को मजबूती मिलती है।

सफलता की कहानी और व्यापक महत्त्व

- ❖ मेघालय के मासिनराम में, जो दुनिया का सबसे नम स्थान है, बंशाइलांग मारबानियांग ने आईआईई द्वारा समर्थित एक खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की स्थापना की।
- ❖ ये उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के दस उद्यमियों में से एक थे, जिन्हें 75वें गणतंत्र दिवस के कर्तव्य पथ समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- ❖ ग्रामीण विकास परियोजनाएँ उद्यम निर्माण को महानगरों से परे गाँवों, छोटे कस्बों व वंचित समुदायों की ओर ले जाती हैं।
- ❖ नौकरी चाहने वालों को नौकरी सृजनकर्ताओं में परिवर्तित करने से रोजगार, सामुदायिक सक्रियता और एक समावेशी, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होता है।

निष्कर्ष

ASPIRE यह दर्शाता है कि लक्षित इनक्यूबेशन ग्रामीण महत्वाकांक्षा को उद्यम, रोजगार एवं समावेशी आत्मनिर्भरता में बदल सकता है।

11. 'कैच द रेन' अभियान : जल-सुरक्षित भारत का निर्माण

परिचय

कैच द रेन अभियान जल-सुरक्षित भारत के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण एवं सामुदायिक प्रबंधन को बढ़ावा देता है।

अभियान की प्राथमिकताएँ और सामुदायिक मॉडल

- ❖ 4 जुलाई से 4 अगस्त, 2026 तक चलाए गए इस अभियान में कटाई, पुनर्भरण, जल निकायों के जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण और जनभागीदारी को तेज किया गया।
- ❖ घरों, समितियों और कार्यस्थलों में वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ स्थानीय वर्षा को विकेन्द्रीकृत जल भंडारण में परिवर्तित करती हैं।
- ❖ मरम्मत किए गए बोरवेल के साथ-साथ पुनर्भरण गड्ढे एवं शाफ्ट जल रिसाव में सुधार करते हैं और भूजल पुनर्भरण को मजबूत करते हैं।
- ❖ बावड़ियों, कुओं एवं पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार करना, जलाशयों से गाद निकालना और वृक्षारोपण करना मानसून के दौरान जल संचयन को मजबूत करता है।
- ❖ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 6 सितंबर, 2024 को सूरत में जल संचय जन भागीदारी (JSJB) का शुभारंभ किया गया।

- ❖ समुदाय (Community), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और लागत (Cost) मिलकर तीन 'सी' (C) बनाते हैं जो संसाधनों के अभिसरण को सक्षम बनाते हैं।

उद्भव और मात्रात्मक उपलब्धियाँ

- ❖ 1 अप्रैल, 2024 से 31 मई, 2025 के दौरान JSJB 1.0 ने कम से कम दस लाख संरचनाओं को लक्षित किया है जिनमें से 27 लाख से अधिक की रिपोर्ट प्राप्त हुई।
- ❖ JSJB 2.0, जिसे 1 जून, 2025 को लॉन्च किया गया था, ने अत्यधिक दोहन वाले और महत्वपूर्ण जिलों में पुनर्भरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया।
- ❖ 31 मई, 2026 तक एक करोड़ संरचनाओं का लक्ष्य रखा गया था, जबकि देशभर में 1.5 करोड़ से अधिक संरचनाओं की सूचना मिली।
- ❖ रिपोर्ट की गई संरचनाएँ लक्ष्य से 50% से अधिक थीं किंतु अभी भी भौतिक सत्यापन और क्षेत्र सत्यापन के अधीन हैं।
- ❖ नवंबर 2025 में आयोजित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में जेएसजेबी 1.0 के अंतर्गत किए गए अनुकरणीय योगदानों को मान्यता दी गई।
- ❖ JSJB : कैच द रेन 3.0, 1 जून, 2026 को लॉन्च किया गया, JSJB को जल शक्ति अभियान के साथ एकीकृत किया गया।

संस्थागत अभिसरण और परिणाम

- ❖ यह अभिसरण विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल-निकाय बहाली को जोड़ता है।
- ❖ क्षतिपूर्ति वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA), वित्त आयोग के अनुदान और राज्य योजनाओं से वित्तपोषण का दायरा बढ़ता है।
- ❖ जिला जल शक्ति केंद्र (JSK) स्थानीय कार्यान्वयन के लिए ज्ञान, तकनीकी मार्गदर्शन एवं योजना संबंधी सहायता प्रदान करते हैं।
- ❖ जनभागीदारी पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, महिलाओं, युवाओं, स्कूलों एवं नागरिक समाज को संगठित करती है।
- ❖ निरंतर वर्षाजल संचयन और पुनर्भरण कृषि, आजीविका, जलवायु अनुकूलनशीलता एवं अंतरपीढ़ीगत जल सुरक्षा को मजबूत करता है।

निष्कर्ष

वैज्ञानिक योजना, स्थानीय भागीदारी और सामूहिक कार्रवाई से जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, कृषि को मजबूत किया जा सकता है और विकसित भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है।